

Government has failed so miserably in calculating the assets and liabilities and all that and, after taking into account the interest of the country, to terminate the contract entered into by Esso. It is a well known fact that Esso will not enter into a contract keeping our national interest. It is after all a foreign company.

Now, what we understand today, when the Government is seeking an extension of period, is that at the time when the Bill was introduced, they were not clear what to do. They thought, within six months, everything will be done. Today, when they seek another extension of six months, this is an admission that they have failed to process to complete all the necessary formalities and to put an end to contract which is not in the interest of the country.

Is this the way the Government should deal with a matter in which the interest of the country versus the multi-national corporations are involved. We feel rather very concerned that it is a very casual manner in which the Bill was introduced and it is the same manner in which the Government is seeking for another extension of period. Can the hon. Minister say that in another six months, he will complete all the formalities? He will not be able to do that. I am sure, he will come again for another extension of time. He should kindly tell us what is the reason for this delay, what prompted the Government not to act expeditiously so that all these contracts could have been terminated within the time they themselves fixed, not fixed by us. What happened? today, the Government should also make it clear what they mean when they say that another extension of six months is required. It means that, for another six months, we will be looted by the contractors who were brought in here for sales or service by ESSO. That means, even after **Esso (Acquisition of Undertakings) Bill** has been adopted, for another year this coun-

try will be mercilessly looted by the contractors who were brought into our country by the old company, ESSO. Will that not be the fact?

Another aspect is that this will hamper the prospects of nationalising other foreign-owned oil companies. The Government stand committed—they have said this in the House as well as outside; they have declared from housetops that this is their policy—to nationalise all foreign-owned oil companies. And in today's context when international cartels are in the dock of world public opinion for their exploitation and developing countries are taking the bold step of nationalising these companies, as has been done by Iraq, by extending the period from six months to one year, I am very sure, we will further slow down this process. If at all there is something in their mind, nationalising foreign-owned oil companies here the process will be slowed down because you could not process their contracts and all that. They could not decide which are the contracts which are in the interest of our country and which are the ones to be terminated. So, for another six months, the fate of the country in relation to foreign-owned oil companies and the programme of nationalisation will be sealed. This is the meaning, as we understand from the attempt of the Government in seeking extension for another six months.

Now I request the hon. Minister to make these points clear: first, what is the reason for the failure of the Government in completing the formalities within six months; secondly, what will be the consequences of giving extension for another six months, whether it will not allow the contractors brought into our country by ESSO to loot our country for another six months; and, lastly, whether this measure will not hamper the prospects of nationalising all foreign-owned oil companies in our country. If these are satisfactorily answered, one will understand what is the programme of nationalising the

foreign-owned oil companies in
country.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) :
सभापति जी, जो मूल बिल इस सदन में
आया था उस वक्त हमने इस के सिद्धान्त,
इसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या होना चाहिए,
आयल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण होना
चाहिए या नहीं होना चाहिए यह सारे बातें
डिस्कस की थीं। अब उन्हीं मुद्दों में फिर
जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा।
यह तो एक बहुत ही मामूली और सादा
बिल है। केवल तीन धाराओं का, जिनमें
टास एक्सटेंशन की बात कही गई है।

विरोधी दलों की ओर से कहा जाता है
कि गवर्नमेंट काम करने में अक्षम नहीं है,
क्यों वेल्योर हुआ उसका कारण नहीं
बताया गया है। हम लोग अबसर देखते हैं
इस हाउस के द्वारा सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती
है और उनको समय दिया जाता है कि
अमुक तारीख तक बिल पर विचार का के उन
को सदन में पेश करें लेकिन अक्सर इस
हाउस में उन लोगों का भी अनुभव है कि उनको
दो तीन बार एक्सटेंशन मिलता है।

इतनी बात तो उसमें आ जाती है कि उनमें
समय में ही नहीं सका है। सरकार भी
इतने थोड़े समय में विचार नहीं कर सकी
और फाइनेलाइज नहीं कर सकी और इसी-
लिये समय बढ़ाने की बात आ रही है।
6 महीने का समय और बढ़ा दिया जाय
ताकि सरकार सोचसमझ कर और अच्छी
तरह जांच कर के उस काम को कर सके।

रही बात लूट की। वह कम्पनी के
समय में सम्भव था। अब सब मामला
सरकार के हाथ में है। और मैं नहीं
समझता कोई सदस्य यह समझे कि सर-
कार लूट करा देगी। लूट रोकने के लिये
ही ऐन्वोजीशन हुआ है और राष्ट्रीयकरण

हुआ है। इसलिये लूट की सम्भावना नहीं
है। हो सकता है इस अवधि में सरकार
कॉन्ट्रैक्ट के सम्बन्ध में जिन पर विचार करना
था, कार्यवाही करनी थी उनका वजह से
नम्र लग सकता है। इसलिये घबरावने
की बात नहीं है। इसलिये इन बिल को
पास करना चाहिये, और वह सब सवाल
किनना रखा गया, किनना रखा आया
यह सब पढ़ने हा हा चुका है। अब सवाल
नहीं उठता है। हा, मंत्री जी बना देने तो
अच्छा होता कि किन्कारणों में वह इस काम
को नहीं कर सके? उसमें मेम्बरों को कुछ
सन्तोष ही जाता। ना यह मान सदस्यों
की जायज है, उसको बना देना चाहिये।

श्री हुकम चन्द कल्लुशव (मुरैना) :

सभापति जी, जो बिल ऐंसा के सम्बन्ध में
हमारे सामने आया है मैं इसका विरोध
करता हूँ। वैसे यह बिल लाने की सरकार
का आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि सरकार
ने जो समय मांगा है समय में नहीं आता
कि सरकार इतना लम्बा क्या खींचना चाहती
है? क्या कम्पनी बलों को और अधिक
संका देना चाहती है कि नाना प्रकार का
घांट ला करे? यदि इन प्रकार की कोई
बात है तो आपने जो निर्णय पहले लिया है
उसी पर कायम रहिये और अधिक समय न
मांगिये। आप कहते हैं कि काफी कठिना-
इयां हैं। आपके पास सब प्रकार के विशेषज्ञ
हैं, योग्य व्यक्ति तथाकथित हैं, तो क्या
प्रारम्भ में इन बात पर विचार नहीं किया
कि हमें समय बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी?

तेल के उद्योग के अन्दर आज सारे देश
में कमी महसूस की जा रही है।
और इस क्षेत्र में एक कठिनाई
बहुत का आवश्यकता है आज ऐसा
लक्षण है कि तेल के बिना जीवन सुरक्षित
नहीं है। चाहे मिट्टी का तेल हो, मोटर का
तेल हो या गैस हो। दिन प्रति दिन इनकी
कमी ही होती जा रही है, इसको हमें